

पत्रांक 874 / 36 सी.  
सेवा में,

दिनांक 12 / 8 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर।

**विषय:-** जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी-पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ:-** इस कार्यालय का पत्रांक सं० 1318/36सी० दिनांक 18/7/2023 महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तों एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है-

क्रम सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं० 01 का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.87 हे० सिविल खसरा न० 1265 एम में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण Notification एवं करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline Para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त सं० 03 का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त सं० 04 का अनुपालन किया जायेगा।
5	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) सं० 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी०(pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०	शर्त मान्य है।

	दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.435 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई का न्यूनतम कर देगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 109 पेड़ से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं० 6 में वांछित धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	अनुपालन किया जायेगा।
8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कटाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
9	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला क्लेकटर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं० 9 एफ०आर०ए० 2006 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार अनुपालन किया गया है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयागकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों का राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं० 17 का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसिया विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त सं० 19 का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के	शर्त सं० 20 का अनुपालन किया जायेगा।



	दिशानिर्देश फाइल सं० 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2019 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग क पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेबारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

संलग्न- 03 प्रातियों में,

९८

अधिशाली अभियन्ता  
नि०ख० लो०नि०वि०  
थराली चमोली

पत्रांक 874/36 सी०

दिनांकित 12/6/2024

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

९८

अधिशाली अभियन्ता  
नि०ख० लो०नि०वि०  
थराली चमोली।

AGENCY COPY

यूनिऑन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-03-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6140272750 ✓
MoEF/S&G File No.	8B/UCP/06/119/2020/FC ✓
Location.	UTTARANCHAL ✓
Address.	Tharali Chamoli ✓
Amount(in Rs)	3200463/- ✓

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Four Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN003710
Pay to Account No.	150396140272750 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma  
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

After making the required payment through che  
even after 7 working days, the user ma  
Email: cb0371@unionbankofindia.com

30 MAR 2022  
Brijesh Jaiswal

Executive Engineer  
Cont. Div - P.W.D  
Tharali (Chamoli)

29/3/22

कोट प्रमोद सिंह

सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड, लोडि रोड  
चमोली (चमोली)



880/252

4/8/2021

आदेश

जनपद चमोली में कुलसारी-नैल-ढालू मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.288 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए विनियत 4.576 हे० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08वीं/यू०सी०पी०/06/119/2020/एफ०सी०/1553 दिनांक 13.10.2020 की शर्त सं०-3(ख) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में कुलसारी-नैल-ढालू मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.288 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम नैणी, रा०उ०नि० क्षेत्र कुलसारी, तहसील थराली की ख०खा०सं०-11 के खसरा सं०-43 रकबा 2.076 हे०, खसरा सं०-53 रकबा 2.109 हे०, खसरा सं०-60 रकबा 0.233 हे०, खसरा सं०-277म० 0.158 हे० अर्थात् कुल 4.576 हे० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य वंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII (II) /2012-18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० मदीरिया),

जिलाधिकारी,

चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 7815

/छबीस-37 (2020-2021) गोपेश्वर: दिनांक: 27 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिसारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, थराली।

जिलाधिकारी,

चमोली।

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
थराली (चमोली)





एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- सनपद चमोली में कुलसारी- नेल -ढालू नोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.248 हे० सिविल, 0.042 हे० वन पंचायत. कुल 2.288 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

खण्ड अधिकारी

अभिप्रेत अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
थराली, (चमोली)

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
थराली (चमोली)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली  
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e\_mail:- pwdtharali@gmail.com



## "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर जहां-जहां संभव हों वहां स्ट्रिप प्लान्टेशन स्वयं के व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
थराली (कमोली)

कोटि रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
थराली (कमोली)





Ph. No :- 01363-271224

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली  
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e. mail :- eecdthrl.pwduk@gov.in



### "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

③  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
थराली (चमोली)

प्रमाणित किया जाता है

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
थराली (चमोली)

